



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 17) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
10 दिसम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(मुक0)—सम0—19—29/2007/1485—श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर से उनके परिक्षेत्राधीन फर्जी कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 230 दिनांक 11.1.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, जिसमें निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:—

(क) वित्त विभाग के परिपत्र 7677 बी0 (9) दिनांक 31.10.2000 के अनुसार फर्जी/अवैध नियुक्ति के आधार पर वेतन भुगतान को अनियमित निकासी माना गया है तथा उस अनियमितता के लिए कार्यालय प्रधान के साथ-साथ नियंत्री पदाधिकारी को संयुक्त रूप से दोषी माना गया है।

(ख) बिहार कोषागार संहिता के भाग-1 के नियम 306 के प्रावधान के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना है, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया गया है।

इसी बीच दिनांक 31.7.04 को श्री चौधरी सेवानिवृत्त हो गये, अतः सरकार द्वारा इनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। तदनुसार उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6419 दिनांक 10.11.04 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त निम्नांकित आरोप श्री चौधरी के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये:—

“अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्रभावी ढंग से नहीं रहा। अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करना चाहिए जो नहीं किया गया।”

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री चौधरी के पेंशन की राशि से 20 (बीस) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक 613 दिनांक 15.6.06 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना सं0—188 दिनांक 7.3.07 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया:—

1. श्री चौधरी के पेंशन की राशि से बीस (20) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी० डब्लू० जे० सी० सं०-7978/07 दायर किया गया जिसमें दिनांक 14.2.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-188 दिनांक 7.3.07 के द्वारा निर्गत दण्डादेश निरस्त कर मामले को जाँच पदाधिकारी(Enquiry officer) को इस आदेश के साथ लौटाया गया कि वे संतुष्ट हो ले कि वित्त विभाग का उक्त परिपत्र 7677 बी० (9) दिनांक 31.10.2000 मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2000-01 में प्राप्त कराया गया है अथवा नहीं।

उक्त पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी को संसूचित दण्डादेश "पेंशन की राशि से बीस (20) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष तक के लिए" से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०-188 दिनांक 7.3.07 को विभागीय अधिसूचना सं०-1370 दिनांक 12.12.12 द्वारा इस शर्त के साथ निरस्त किया गया कि न्यायादेश के आलोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से यह आदेश प्रभावित होगा।

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर मामले की जाँच करायी गयी। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि वित्त विभाग का उक्त परिपत्र श्री चौधरी को वित्तीय वर्ष 2000-01 में ही प्राप्त था। अतः उनके विरुद्ध अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने तथा अधीनस्थों पर नियंत्रण के अभाव का आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

1. पेंशन से बीस (20) प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए।

सरकार का उक्त निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नागेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 17-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>